

EDITORIAL

Massive Indefinite Strike

The AUAB has taken a decision to go on indefinite strike from Dec. 3rd, 2018 demanding implementation of wage Revision, 4G, Pension Revision, pension contribution and settling some 2nd PRC issues.

The struggle for wage revision is getting on three tracks. The first one is joint struggle of both Executives and Non Executives on the platform of AUAB for seeking relaxation of affordability clause, a conditional clause in the order of Executives and 3rd PRC. The second is purely by Non-Executives in their wage Committee to arrive at the necessary agreement or MOU to implement wage revision for Non-Executives. The third one is the struggle of all central unions like AITUC, CITU, INTUC, LPF etc. for abolishing and nullifying the applicability clause.

The immediate provocation for announcing the indefinite strike is the tone and tenor of DOT's directive letter dated 6th Nov, after some assurances by Secretary DOT on 2nd Nov. The subject matter of the letter is having only the reference of Executives but the content speaks for both Executives and Non-Executives. The main directive of DOT is advising BSNL to re examine their proposal sent for Executives on their varied observations and analysis. The main issue is dip in revenue growth and increase of Expenditure on account of wage revision if implemented with 15%. The other question is about resources shown by BSNL which one is based on speculation and not on the basis of real grounds.

Unfortunately DOT is conveniently not cared and set aside its own version submitted in the Lok Sabha Committee on petitions. The reasons cited by DOT for the decrease in Revenue in the BSNL are

- a) Fixed to mobile substitution
- b) Stiff competition in the mobile sector
- c) Frequent downward revision of tariff
- d) Outgo of payment 18500 cr towards 3G/BWA
- e) Reduction of reserves and Balance and so reduction in interest income
- f) Premature withdrawal of ADC

- g) License Fee Non Imbursement
- h) Withdrawal of other subsidies and compensation

In the same way DOT has listed reasons for enhancement of Expenditure in the BSNL

- a) Huge legacy of work force whose salary and benefits is above 50% of revenue
- b) Inheritance of legacy wire lines and its maintenance
- c) Economically unviable rural operations as social obligations
- d) Increase in fuel charges
- e) Increased repair and maintenance cost

As per BSNL version, the company has spent 1.75 lakh crore on the salary head for this legacy of work force. The role of BSNL as priority sector specified by Finance commission was also not taken into account. Almost all the heads of SSAs/ Circles got their wage revision on the basis of 7th CPC and DOT never cared about financial viability of BSNL and gave green signal to BSNL for implementing the same to its own ITS officers.

The inflation is the main reason for increase of salary expenditure. Frequent downward revision of tariff is the main reason for making the services cost ineffective.

The issue of 4G is being dragged months together. BSNL has demanded 2100 MHZ for more than 20 circles as AirTel, Reliance JIO, Idea are already capturing 4G market. As on last December already 24 crore 4G subscribers were added by the private Telcos. In this background one can understand the urgency of getting 2100 Mhz spectrum by BSNL for marketing 4G services.

The other issue is pension revision. Almost all the unions and associations are having consensus that the issue need not be dragged on the plea of pay revision. The issue should be settled in such a way that there should not be any anomaly either for the past pensions or for the future pensioners. Unfortunately DOT has issued a letter on 16-3-17 stating as there is no change in pension formula, BSNL/MTNL absorb employees will therefore continue to get pension based



on the same formula. Many of our lower scale employees are being affected by this as they will get less pension than the minimum Rs 9000.

The issue of pension contribution is also getting dragged since long . As per the PIB issued when MTNL pension was included in the same category of 37 A, it was stated that the MTNL contribution for Pension could be as per actual pay from 2006 onwards. Unfortunately this position was not extended to BSNL.

Taking all these factors into account, the unions and associations have given a call for indefinite strike. Our CHQ appeals to one and all to make the strike success.



प्रचण्ड अनिश्चितकालीन हड़ताल

बीएसएनएल में कार्यरत सभी यूनियन एवं एसोसिएशन की एक महान एकता के तहत दिनांक 3 दिसम्बर 2018 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। यह हड़ताल सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए तृतीय वेतन पुनरीक्षण, सेवा विस्तार हेतु 4जी स्पेक्ट्रम का आवंटन, पेंशन – पुरीक्षण, वास्तविक वेतन दर पर पेंशन अंशदान की वसूली, एवं द्वितीय वेतन पुनरीक्षण के वंचित मामलों को निराकरण यानी कुल पांच मांगों के लिए किये जा रहे हैं।

अभी आगत श्रमिक आंदोलन तीन पथगामी है। प्रथम सभी एकजीक्यूटिव कर्मियों के लिए तीसरा पे रिवीजन, द्वितीय नॉन एकजीक्यूटिव कर्मचारियों के हित में तीसरे वेज रिवीजन में आंदोलन बीएसएनएल के सभी यूनियन और एसोसिएशन एकजुट होकर कर रहे हैं तीसरा आंदोलन समस्त केन्द्रीय श्रम संगठनों यथा, एटक, इंटक, सीटू, एक्टू, यू.टी.यू.सी, एल.पी.एफ. आदि ग्यारह राष्ट्रीय संगठनों ने नये साल के 8 एवं 9 जनवरी को राष्ट्र हड़ताल की घोषणा की है।

आक्रोशित कर्मचारियों को दूरसंचार विभाग के पत्र दिनांक 6 नवम्बर 2018 ने आग में घी डालने का काम किया है और कर्मचारियों – अधिकारियों को ज्यादा उद्वेलित किया है, परिणामतः 3 दिसम्बर 2018 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का कर्मचारियों ने फैसला लिया है। डी.ओ.टी. ने बीएसएनएल प्रबंधन से एकजीक्यूटिव कर्मचारियों के लिए भेजे गये प्रस्ताव की पुनःजांच के लिए कहा है। डी.ओ.टी. ने राजस्व में गिरावट एवं 15% फिटमेंट के साथ तृतीय वेतन पुनरीक्षण लागू करने में खर्च में भारी बढ़ोत्तरी का जिक्र किया गया है। डी.ओ.टी. ने बीएसएनएल द्वारा बताये गये संसाधन को काल्पनिक बताया है।

दुर्भाग्यवश डी.ओ.टी. ने स्वयं द्वारा लोक सभा समिति को सुपुर्द किये गये वाक्यों को भूल गई है, जिसमें उसने कहा है कि –

- 1) मोबाइल सेवा प्रतिष्ठापन के लिए जड़ित।
- 2) मोबाइल क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा।

- 3) टैरिफ का लगातार निम्नवत संशोधन
- 4) 3जी/बी.डब्ल्यू के लिए 18500 करोड़ रु. की लागत
- 5) रिजर्व और बैलेंस में कमी के कारण ब्याज की कमी।
- 6) ए.डी.सी. की समय पूर्व वापसी।
- 7) लाइसेंस शुल्क गैर संवर्धन।
- 8) अन्य सबसिडी एवं क्षतिपूर्तिकरण की वापसी।

इसी प्रकार डी.ओ.टी. ने बीएसएनएल में खर्च में बढ़ोत्तरी को सूचीबद्ध किया गया है।

- 1) कर्मचारियों की विशाल संख्या जिसके वेतन पर राजस्व का 50% खर्च है।,
- 2) तार-लाइनों और उसके रख-रखाव की विरासत।
- 3) सामाजिक दायित्व के नाम पर आर्थिक रूप से।
- 4) ईंधन दर में वृद्धि।
- 5) रखरखाव एवं मरम्मत खर्च की वृद्धि।

बीएसएनएल के अनुसार कम्पनी ने कर्मचारियों के वेतन भत्ते के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपये खर्च किये हैं। वित्त आयोग द्वारा बीएसएनएल को प्राथमिकता के क्षेत्र में रखने के अनुशांसा को भी डी.ओ.टी. ने नजरअंदाज कर दिया।

सभी सर्किल एवं एस.एस.ए. शीर्ष अधिकारियों को 7वें वेतन आयोग के निर्णय के अनुरूप लाभ देने के लिए डी.ओ.टी. ने बीएसएनएल के वित्तीय स्थिति का सवाल और उनको बढ़े वेतनमान देने के लिए हरी झंडी दिखा दिया।

राष्ट्रीय मुद्रा स्फिति खर्च में बढ़ोत्तरी का मुख्य कारण है। सेवाओं के लागत को अप्रभावी बनाने का मुख्य कारण टैरिफ का लगातार निम्नवत संशोधन है।

4जी आवंटन के मुद्दे को महीनों से टाला जा रहा है। बीएसएनएल ने 2100 मेगाहर्ट्ज की मांग की है। 20 से अधिक सर्किलों के लिए होगा। जबकि रिलायंस जिओ, एयरटेल, आइडिया ने पूर्व गतवर्ष दिसम्बर माह तक 24 करोड़ 4जी उपभोक्ता को निजी कम्पनियों ने जोड़ लिया है। अब यह कोर्ट भी समझ सकता है। कि इस परिस्थिति में 4जी स्पेक्ट्रम बीएसएनएल के लिए कितना जरूरी है।

एक मुद्दा पेंशन संशोधन का है। सभी यूनियन और एशोसिएशन का मत है कि पेंशन पुनरीक्षण को वेतन पुनरीक्षण के नाम पर विलम्बित करना न्यायसंगत नहीं है। इस मुद्दे का समाधान ऐसा हो कि पूर्व के पेंशनभोगियों और भविष्य के पेंशनभोगियों के बीच किसी प्रकार की विसंगति नहीं हो।

डी.ओ.टी. ने दिनांक 16.3.2017 को एक पत्र के द्वारा कहा है कि पेंशन फार्मूला में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए पुराने फार्मूले पर ही पेंशन संशोधन किये जायेंगे। इस से निम्न वेतन भोगियों को निर्धारित पेंशन 9000 रुपये से कम की राशि मिलेगी।

पेंशन अंशदान का मुद्दा भी बहुत लंबे अर्से से लटककाया गया है।

एम.टी.एन.एल. कर्मचारियों को जब पेंशन नियम -37 ए. के तहत शामिल किया गया तो यह कहा गया कि पेंशन अंशदान वास्तविक वेतन पर देय होगा परन्तु यह नीति बीएसएनएल के लिए नहीं लागू की गई।

हमारी पांचवी मुद्दा नये भर्ती कर्मियों के लिए द्वितीय वेतन पुनरीक्षण के बकाये मामले से संबंधित है, जिसकी पूर्ति करने की मांग संगठनों ने किया है।

इन परिस्थितियों में यूनियन एवं एशोसियेशन ने 3 दिसम्बर 2018 से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है। मुख्यालय का आह्वान है कि एक-एक साथी अगगत हड़ताल में भाग लेकर इसे सफल करें।

